SHRI PRASANNA ACHARYA: Sir, recently the Union Government has taken a decision to close down the oldest Government of India Text Books Printing Press of the country that is located at Bhubaneswar. I do not know why. This Press was established with the help of German Government.

MR. CHAIRMAN: Zero Hour is over.

DR. SANTANU SEN (West Bengal): What about my privilege motion? ...*(Interruptions)*...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY (West Bengal): Sir, he has given a privilege motion. ...*(Interruptions)*... What happened to that? ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: You can't stand like that and abrupt the proceedings. ...*(Interruptions)*... As and when I take a decision, I will let you know and give an opportunity to you.

---

## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

### टोल प्लाज़ा की फास्ट टैग लेन

***196. श्री ओम प्रकाश माथुर :** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों, विशेषकर राजस्थान से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाज़ा पर फास्ट टैग लेन की शुरूआत हो चुकी है; और

(ख) यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री नितिन जयराम गडकरी):** (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

***विवरण***

(क) और (ख) जी हाँ, देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर 479 शुल्क प्लाजा कार्य कर रहे हैं। 409 शुल्क प्लाजाओं में फास्ट टैग लेन कार्य कर रही हैं। राजस्थान राज्य में 69 शुल्क प्लाजाओं में से, राष्ट्रीय राजमार्गों पर 48 शुल्क प्लाजाओं में फास्ट टैग लेन कार्य कर रही हैं। शेष टोल प्लाजाओं पर अपेक्षित अवसंरचना के संस्थापन के कार्य वर्तमान वर्ष के दौरान पूरा करने का प्रस्ताव है।

**FAST Tag lanes of toll plazas**

†*196. SHRI OM PRAKASH MATHUR: Will the Minister of ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS be pleased to state:

(a) whether FAST Tag lane has been made operational at toll plazas of all national highways in the country, especially those passing through Rajasthan; and

(b) if not, by when this task would be completed?

THE MINISTER OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (SHRI NITIN JAIRAM GADKARI): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

(a) and (b) Yes, Sir. There are 479 fee plazas operational on National Highways (NHs) across the country. FASTag lanes have been made operational at 409 number of fee plazas. In Rajasthan State, out of 69 fee plazas, FASTag lanes are operational in 48 fee plazas on National Highways. The work on installation of requisite infrastructure on the balance toll plazas is proposed to be completed during the current year.

**श्री ओम प्रकाश माथुरः** सभापति महोदय, मंत्री जी ने जानकारी दी है कि अभी कुछ फास्ट टैग वाली बननी बाकी हैं, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि उसमें संचालित कितने हैं? अभी भी जो फास्ट टैग वाली lanes हैं, उनमें प्राइवेट गाड़ियां, कैश पेमेंट करने वाली गाड़ियां, और ...(व्यवधान)...

**श्री सभापतिः** प्लीज़, शांति बनाए रखें।

**श्री ओम प्रकाश माथुरः** उसमें ट्रक तक घुस जाते हैं। जिस व्यक्ति ने फास्ट टैग का एडवांस में पैसा दिया है और जो already फास्ट टैग के कार्ड का धारक है, उसको वहां घंटों रुकना पड़ता है। कई बार वहां पर जाम हो जाता है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इसके बारे में जानकारी ली है? अगर उनको जानकारी लेनी है तो यहां से जयपुर की तरफ निकलते ही पहला टोल प्लाज़ा जो हरियाणा में आता है, वहां पर आप कभी भी देख लीजिए कि lanes बनी हुई हैं, लेकिन उनमें प्राइवेट गाड़ियां भी घुस जाती हैं, तो इसको रोकने के लिए क्या व्यवस्था की गई है?

**श्री सभापतिः** आपका सवाल क्या है?

**श्री ओम प्रकाश माथुरः** सभापति महोदय, मेरा सवाल यही है कि जो आपने फास्ट टैग वाली lanes बनायी हैं, उनमें से कितनी संचालित हैं और वास्तव में उनमें फास्ट टैग वाली गाड़ियां ही जाती हैं या प्राइवेट गाड़ियां भी जाती हैं?

**श्री नितिन जयराम गडकरीः** सभापति महोदय, सम्माननीय सदस्य ने जो बात बताई है, वह तथ्यात्मक है। इसका कारण है कि इसमें अभी टोटल पब्लिक फंडेड 159 और पी.पी.पी. में 274 है, तो इसमें अभी काफी जगह पर दो lanes हुई हैं, कहीं तीन lanes हुई हैं और कहीं पर अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। इसमें दो-तीन साल से हमने जो प्रयास किया था, उसमें सॉफ्टवेयर, बैंकों की इन्वॉल्वमेंट

† Original notice of the question was received in Hindi.

[श्री नितिन जयराम गडकरी]

और फिर बैंक में यह फास्ट टैग मिलते थे। इस तरह की दिक्कतों के कारण यह ठीक से नहीं चल रहा था ओर यह काफी जगह पर फेल हुआ। अभी हमने यह तय किया कि इसके बाद 100 परसेंट टोल प्लाज़ा को 6 महीने के अंदर पूरी तरह से फास्ट टैग पर ले जाएंगे। एक बात यह अच्छी हुई है कि दिसम्बर के बाद आप कोई भी नई गाड़ी खरीदेंगे तो उस पर रेडीमेड फास्ट टैग लगकर आएगा। इसमें बहुत ज्यादा काम करना है, ऐसा नहीं है। अगस्त 2017 में, 6.32 लाख फास्ट टैग बेचे गए थे और अब इनकी संख्या 26.46 लाख हो गई है। हम इसको पूरी तरह से 100 परसेंट करेंगे और 6 महीने के अंदर seamless traffic होगा। जो दिक्कतें सम्माननीय सदस्य ने बताई हैं, वे सही हैं। इसके बारे में मुझे भी जानकारी है। इसमें सॉफ्टवेयर और बाकी बातें भी हैं। एक छोटी सी बात यह है कि हम स्टेट गवर्नमेंट को भी यह पूरा सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं।

**श्री ओम प्रकाश माथुरः** सभापति महोदय, इसके साथ ही कुछ सांसदों को और हमको अपने क्षेत्र की गाड़ियों के लिए दो टैग और दे रखे हैं। लेकिन उसकी समुचित व्यवस्था न होने से, जब उनके परिवार के सदस्य गाड़ी लेकर निकलते हैं, तो उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार होता है। हमको ऑफिशियल फास्ट टैग दिया गया है। हमारे परिवार के सदस्य जहां भी जाते हैं, अब सांसद तो वहां नहीं हैं, सांसद तो यहां संसद में हैं, लेकिन वहां पर जिस प्रकार उनके परिवार के लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है और उनमें महिलाएं भी होती हैं, उनके साथ भी दुर्व्यवहार होता है, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इसको रोकने के लिए कोई व्यवस्था है?

**श्री नितिन जयराम गडकरीः** सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि हर मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट को दो टैग दिए गए हैं। एक दिल्ली के लिए है और एक उनकी constituency के लिए है। उनकी constituency में जो टैग उनकी गाड़ी में लगा हुआ है, उसमें जो भी लोग बैठेंगे उनके लिए फ्री है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात यह है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि MPs के साथ में पांच-छह गाड़ियां आती हैं, वह इनकी गाड़ी के लिए तो फ्री ऑफ चार्ज है, बाकी गाड़ियों के लिए नहीं है। एक राज्य उसका मैं नाम नहीं लूंगा, जहां पर गाड़ी पर लाल 'दिया' लगता था, उसे हमारे डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दिया, तो कुछ राज्यों में हमारी टोल इन्कम बढ़ गई, क्योंकि जो लोग यह 'दिया' लगाने वाले होते थे, वे भी अधिकृत नहीं होते थे और वे टोल पर निकल जाते थे। हमने अभी दो टैग दिए हैं, अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे बताएं, मैं उस पर कार्रवाई करूंगा।

MR. CHAIRMAN: Members concerned can also write. Now, Shri Sanjay Raut.

**श्री संजय राउतः** सर, मैं मंत्री जी के उत्तर को विस्तार से पढ़ रहा था और उनके उत्तर को सुन रहा था। उनका जो रिटन रिप्लाई है, वह बहुत ही short है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सवाल है कि जो रिप्लाई आपने अब दिया है, वही रिप्लाई आपने छह महीने पहले भी दिया है। मैंने उसको पढ़ा है, वह चाहे सदन में हो या बाहर हो। आपने कहा था कि आने वाले दिनों में लगभग 3,500 फास्ट टैग लेन्स हो जाएंगी।

**श्री सभापतिः** आपका सवाल क्या है?

**श्री संजय राउतः** सर, मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है कि अब तक कितने टोल प्लाजा में फास्ट टैग लेन्स हुई हैं और उनमें से फास्ट टैग लेन्स महाराष्ट्र में कितनी हैं? आज भी महाराष्ट्र में चाहे मुम्बई-नासिक हो, चाहे मुम्बई-पुणे हो, वहां पर बहुत कठिनाई है, कोई सेपरेट लेन नहीं है और जब भी हम वहां से जाते हैं, तो वहां की मशीन फेल है।

**श्री सभापतिः** महाराष्ट्र में कितना है? आप यह बताइए।

**श्री संजय राउतः** महाराष्ट्र में कितना है और देश में आप कितना बढ़ाने जा रहे हैं?

**श्री नितिन जयराम गडकरीः** सर, महाराष्ट्र में जो मुम्बई-पुणे एक्सप्रेस हाइवे है, जब मैं महाराष्ट्र में था, तब बनाया गया था, उसका संबंध गवर्नमेंट से है। वह भारत सरकार का राष्ट्रीय महामार्ग नहीं है। जो बात आपने मुम्बई-नासिक की कही है, मैं यह स्वीकार करता हूं कि इस सिस्टम में, जैसे चार-पांच chef एक जगह आ कर के पूरे किचन को spoil कर रहे हैं, वैसे ही इसमें तीन-चार साल में इतने अलग-अलग प्रकार के ज्ञानी लोग आये और उन्होंने इतने सॉफ्टवेयर दिए और उसमें बैंक से खरीदने की बात थी, वह पूरा सिस्टम फेल हो गया। मैं यह स्वीकार करता हूं कि जिसके बारे में सम्माननीय सदस्य कह रहे थे और इसीलिए इसके बाद हमने निर्णय किया कि हंड्रेड परसेंट को ये करेंगे और इसमें 24 जगह पर ऐसा है कि 107 जगहों पर दो लेन्स हैं, कुछ जगहें ऐसी हैं, जिनका काम अभी शुरू हुआ है। महाराष्ट्र के बारे में डिटेल्स मेरे पास नहीं हैं, मैं पूरी डिटेल्स माननीय सदस्य को भेज दूंगा।

**श्री सभापतिः** आप डिटेल्स इकट्ठी करके माननीय सदस्य को भेज दीजिए। श्रीमती विजिला सत्यानंत। मुझे 'सबका साथ, सबका विकास' का ख्याल रखना है।

SHRIMATI VIJILA SATHYANATH: Sir, my direct question to the hon. Minister is that at all the toll plazas, people suffer like anything. This is an untold suffering. Actually, fast tag lane and all, is not at all in operation. Nothing is okay.

MR. CHAIRMAN: What is your question?

SHRIMATI VIJILA SATHYANATH: What I am saying is, kindly abolish all the toll tax.

MR. CHAIRMAN: How is it possible?

SHRIMATI VIJILA SATHYANATH: The people will praise. Will the Minister take away or remove, in a phased time, all the toll plazas all over the country? People will really praise you, hon. Minister.

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister please reply. Madam, आप बैठ जाइए।

SHRI NITIN JAIRAM GADKARI: Sir, if you want good services, you have to pay for it. Without toll, we cannot construct express highway and road. Just five days before, the Chairman of the State Bank of India gives me a cheque of ₹25,000 crore. Why is he

[Shri Nitin Jairam Gadkari]
giving this money to us? It is because our credibility is higher. Our rating is AAA. We have to take that money from that toll and we have to construct the roads. We don't have any other option. It is difficult to abolish.

MR. CHAIRMAN: Thank you. Now, Shri Prabhakar Reddy Vemireddy.

SHRI PRABHAKAR REDDY VEMIREDDY: Sir, I request the hon. Minister to tell whether the GST, which they are charging on toll can now, be reduced to the service charge which was previously 15 per cent, which now they have made it 18 per cent. This tag is actually a new thing which we are introducing in the country. So, should we put it to the GST Council and reduce the tax?

MR. CHAIRMAN: Right. It is a separate question. But, anyhow, if the hon. Minister wants to respond, he can.

SHRI NITIN JAIRAM GADKARI: This has been referred to the Finance Ministry. They are probably going to resolve this issue. But, now, before GST, there were also some taxes applied. That is the reason why the Finance Ministry is arguing that we were paying taxes even before. Still, we are discussing the issue with the Finance Ministry. We will find out a way.

MR. CHAIRMAN: Now, Question No. 197. Shri Ravi Prakash Verma. We are admitting 15 questions but we are not reaching up to 10. So, I have to see that.

**Contamination of ground water due to soak pits in toilets**

*197.SHRI RAVI PRAKASH VERMA: Will the Minister of DRINKING WATER AND SANITATION be pleased to state:

(a) the details of soak pits being used in toilets under Swachh Bharat Mission (SBM) in the country along with the cost thereof;

(b) whether Government is aware that ground water is being contaminated due to use of soak pits in toilets which would lead to non-potable drinking water;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the details of corrective measures proposed in this regard?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT; THE MINISTER OF PANCHAYATI RAJ; AND THE MINISTER OF MINES (SHRI NARENDRA SINGH TOMAR): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.